राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प 1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 23-10-19

-::अधिसूचना::-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.स	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान	सिविल मामलों के लि क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बालोतरा	बाड़मेर	बालोतरा	राजस्व जिला बाड़मेर
2.	अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	राजस्व जिला झालावाड़

नोट:- वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ का नाम परिवर्तित कर क्रमश: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बालोतरा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, झालावाड़ निर्धारित करती है।

उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

23.10.19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

[illegible]

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/05/2017(S)/1544 Dated: 31/10/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judge/s.
3. Concerned court/s.
4. concerned Chief Judicial Metro. Magistrate/s.
5. A.O.J. Confidential/ RJS(Estt)/ SC (Estt)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ Computer cell with a direction to upload the same on High Court website)

31.10.19

REGISTRAR (RULES)